भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3107 का उत्तर

स्टेशन पुनर्विकास के लिए पीपीपी मॉडल

3107. श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक निजी मॉडल के तहत पुनर्विकास के लिए चिन्हित रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है;
(ख) स्टेशन पुनर्विकास के लिए पीपीपी मॉडल के अंतर्गत अब तक कुल कितना निवेश प्रस्तावित और प्राप्त हुआ है;
(ग) इन परियोजनाओं में शामिल निजी संस्थाओं की सूची क्या है तथा उनके चयन के मानदंड क्या हैं;
(घ) सरकार और निजी कंपनियों के बीच राजस्व-साझाकरण तंत्र सहित किस वित्तीय मॉडल का पालन किया जा रहा है;
(ङ) अब तक पीपीपी मॉडल के तहत सफलतापूर्वक पुनर्विकास किये गये रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं;
(च) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई;
(छ) पीपीपी मॉडल के तहत स्टेशन पुनर्विकास से अपेक्षित प्रमुख लाभ क्या हैं; और
(ज) पीपीपी आधारित पुनर्विकास को क्रियान्वित करने में क्या चुनौतियां हैं तथा उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए "अमृत भारत स्टेशन योजना" शुरू की गई है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे रेलवे

स्टेशनों तक पहुंच में सुधार लाना, परिचलन-क्षेत्र, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकता अनुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, स्वच्छता, निशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणालियों, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लैंडस्केपिंग आदि के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और इन्हें विभिन्न चरणों में कार्यान्वित करना शामिल है।

इस योजना में रेलवे स्टेशन इमारत में सुधार, शहर के दोनों छोर के साथ रेलवे स्टेशन को एकीकृत करने, मल्टीमोडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी-रहित पटरियों की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार 'रूफ प्लाज़ा' और लंबी अवधि में रेलवे स्टेशन पर सिटी सेंटर की चरणबद्ध योजना व व्यवहार्यता और निर्माण की भी संकल्पना की गई है।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है।

रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के विकास के विभिन्न मॉडलों का अन्वेषण किया है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल है। फिलहाल सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर विकास के लिए 15 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। परियोजना निर्माण एक जटिल और पुनरावर्ती प्रक्रिया है, जिसमें इष्टतमीकरण की आवश्यकता होती है और इस समय सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संबंध में निर्दिष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता।

रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा को अंतर्ग्रस्त करते हुए जटिल स्वरूप का होता है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघनों, अतिक्रमणों को स्थानांतरित करना यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी मैदानी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में व्यवसाय और वित्तपोषण मुद्दों के अतिरिक्त पहलू भी होते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित और चालू कर दिया गया है।

सामान्यत: अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार अथवा रेलवे स्टेशन-वार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 12,994 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आबंटन किया गया है तथा 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान 10,586 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया जा चुका है।

*****